**मध्य प्रदेश वस्त्र निगम के विरुद्ध मामले दायर किया जाना**

473. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगम के 7 कपड़ा मिलों द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण कुछ पार्टियों ने मध्य प्रदेश वस्त्र निगम के खिलाफ मामले दायर किये हैं; और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या और मामले दायर करने वालों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश वस्त्र निगम ने भी ऐसी कुछ पार्टियों तथा फर्मों के विरुद्ध मामले दायर किये हैं जिन्होंने उनको सप्लाई किए गये माल के लिए भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उन पार्टियों के नाम क्या हैं;

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**इन्दौर-मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर द्वारा रंगाई और छपाई के सामान की खरीद**

474. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मंत्री कपड़ा निगम (मध्य प्रदेश) द्वारा ग्रे और तैयार कपड़े की बिक्री के बारे में 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1976 से जून, 1979 तक की अवधि में इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर द्वारा कितनी कितनी मात्रा में और किन किन पार्टियों से रंगाई छपाई का सामान, कपड़े प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले कैमीकल, मशीनरी व साइजिंग में प्रयोग होने वाला सामान, स्टेशनरी व प्रिंटिंग का सामान खरीदा गया और नियमानुसार उसके भुगतान की अवधि क्या है और पार्टियों को कितनी अवधि में भुगतान किया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि 25,000 रुपये से ऊपर का भुगतान वस्त्र उद्योग निगम इन्दौर के चेयरमैन से मिलने के बाद किया जाता है, और यदि हां, तो उपयुक्त अवधि में ऐसे कितने भुगतान किये गये और उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनको भुगतान 4 माह से ऊपर की अवधि में किया गया;

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) मांगी गई जानकारी काफी विस्तृत है तथा इससे निकलने वाला परिणाम इसको एकत्रित करने में लगने वाली परिश्रम के अनुकूल नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं। मिलों द्वारा सहायक निगम को सूचित किए बिना ही सीधे भुगतान कर दिया जाता है। मिलों से उन मामलों में भुगतान करने को कहा गया था जिनमें संभरणकर्ताओं ने सहायक निगम से संपर्क किया था। जनवरी, 1976 से जनवरी 1979 की अवधि के दौरान इस प्रकार के किए गये भुगतानों की संख्या तथा जिन पार्टियों को 4 माह की अवधि के उपरांत भुगतान किया गया था उनके नामों से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

**जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना**

475. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान कितने जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और इन केन्द्रों से कितने व्यक्तियों को काम मिलने की संभावना है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)**: देश के 399 जिलों में से 346 जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई है। इन 346 जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन लगभग 358 जिले आएंगे। कुछ राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में एक जिला केन्द्र के अधीन एक से अधिक जिले आते हैं। योजना में महानगरीय शहरों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शुरू करने का विचार नहीं है। इस तरह से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद व हैदराबाद आदि जैसे महानगरीय क्षेत्रों को इस योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। आशा है कि अगले कुछ महीनों में देश के शेष जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

194 जिला उद्योग केन्द्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1978-79 में 1,46,695 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए थे। जिला उद्योग केन्द्रों से कहा गया है कि वे ऐसी कार्यवाही योजनाएं तैयार करें जिनमें संबंधित जिले की मांग कार्यकुशलता व अतिरिक्त संसाधनों और खण्डवार कार्यक्रम के ब्यौरे उपलब्ध कराने तथा कामगरों पर आधारित क्रियाकलापों, छोटे व लघु एककों, के लिए अलग से वित्तीय, नियोजन व उत्पादन संभव्यताओं का पता लगाने पर ध्यान दिया जाय। आशा है कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र लगभग 2500 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा जिससे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।